उत्तराखंड के लिए विकास और विश्वास का नया साल

उत्तराखंड में परिवार रजिस्टर की जांच के आदेश

दिव्य हिमगिरि

हिमालयी राज्यों की पहली साप्ताहिक पत्रिका

नज़र सब पर

15th ANNIVERSARY

वर्ष 15 | अंक 33 | मूल्य 05 रुपये | 04-10 जनवरी, 2026

मंत्री के पति के 'शर्मनाक बोल' से सियासी घमासान

वर्ष 15 | अंक 33

दिव्य हिमगिरि

04-10 जनवरी, 2026

संपादक
डॉ. कुँवर राज अस्थाना

वरिष्ठ संवाददाता
शंभूनाथ गौतम

संवाददाता
पूनम आर्या

विज्ञापन
सुनील सेमवाल

ग्राफिक डिजायनर
देव भट्ट

संवाददाता
हरिद्वार: डॉ. रजनीश गौतम
पौडी: रत्नमणि भट्ट
कोटद्वार: के.पी. बौंठियाल
रूद्रपुर: हेमचन्द्र बुडलाकोटी
चमोली: मुकेश रावत
रुड़की: श्रीगोपाल नारसन
नैनीताल: शीतल तिवारी
अल्मोड़ा: संजय कुमार अग्रवाल (एड.)
विकासनगर: अजय शर्मा
प्रसार: रमेश सिंह रावत

संपादकीय कार्यालय : 6, म्युनिसिपल रोड, बाला हिसार स्कूल के सामने, डालनवाला देहरादून (उत्तराखंड)
मोबाइल : +91 8433456398, 9410353164
Email: divyahimgiriddn@gmail.com

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक एवं मुद्रक कुँवर बहादुर अस्थाना द्वारा सरस्वती प्रेस, 2, ग्रीन पार्क, निरंजनपुर, देहरादून से मुद्रित तथा 39/7 ई, ई. सी. रोड, (निकट मार्शल स्कूल सीनियर विंग) देहरादून-248001 उत्तराखण्ड से प्रकाशित।
संपादक: कुँवर बहादुर अस्थाना*
*(पीआरबी एक्ट के तहत प्रकाशित सामग्री के लिए उत्तरदायी)

कॉलेज में रैगिंग-एक छात्रा, कई आरोपी और एक असफल व्यवस्था

इससे बड़ी विडंबना क्या होगी कि कोई विद्यार्थी अपना भविष्य बेहतर बनाने के सपनों के साथ किसी कालेज में दाखिला ले और वहां परिचय के नाम पर होने वाली प्रताड़ना की वजह से उसकी जान चली जाए। उच्च शिक्षण संस्थानों में किसी भी तरह की रैगिंग के चलन पर पाबंदी है, लेकिन आज भी इसके बहाने अलग-अलग रूप में विद्यार्थियों को जानलेवा शक्ल में प्रताड़ित किए जाने की घटनाएं अक्सर सामने आती रहती हैं। हिमाचल प्रदेश में एक छात्रा के साथ रैगिंग का जैसा मामला सामने आया है, उससे फिर यह सवाल उठा है कि किसी भी रूप में इस चलन का जारी रहना शिक्षा से लेकर समाज तक के कितने हित में है। साथ ही, तमाम सख्ती के बावजूद आज भी इस पर रोक क्यों नहीं लग सकी है? गौरतलब है कि धर्मशाला स्थित एक कालेज की तीन छात्राओं के खिलाफ रैगिंग और मारपीट, जबकि एक प्रोफेसर के विरुद्ध पीड़ित छात्रा के यौन उत्पीड़न के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। दर्ज मामले के मुताबिक, बीते 18 सितंबर को पिटाई और प्रताड़ना की वजह से पीड़ित छात्रा की हालत बिगड़ गई और इलाज के दौरान 26 दिसंबर को उसकी मौत हो गई। इस घटना में शर्मनाक यह भी है कि कालेज के जिस प्राध्यापक को उत्पीड़न की घटना को रोकना चाहिए था, वह खुद भी छात्रा को प्रताड़ित करने में शामिल हो गया। इस घटना में संस्थान भी कठघरे में है, क्योंकि वहां का प्रबंधन रैगिंग के नाम पर होने वाली ऐसी हरकतों पर लगाम लगाने में नाकाम रहा। हिमाचल प्रदेश में यह कोई पहली घटना नहीं है, जिसमें किसी विद्यार्थी को रैगिंग की वजह से जानलेवा हद तक यातना दी गई। करीब डेढ़ दशक पहले राज्य में कांगड़ा के एक कालेज में मेडिकल पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष के छात्र अमन काचरू के साथ वहीं के चार वरिष्ठ छात्रों ने रैगिंग के दौरान मारपीट की थी, जिसके बाद उसकी जान चली गई थी। ऐसी कई घटनाओं के जैसे त्रासद नतीजे सामने आए, उससे एक व्यापक बहस खड़ी हुई कि उच्च शिक्षण संस्थानों में नवागंतुक विद्यार्थियों की रैगिंग को क्यों नहीं तुरंत खत्म किया जाना चाहिए। इसी क्रम में कानून के तहत शिक्षण संस्थानों में रैगिंग पर प्रतिबंध लगाए गए और खुद सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि अगर शिक्षण संस्थानों में रैगिंग की किसी भी तरह की कोई घटना होती है, तो इसकी जिम्मेदारी संस्थान के प्रमुख पर होगी। यह समझना मुश्किल है कि कालेज में कुछ वरिष्ठ कहे जाने वाले विद्यार्थियों के भीतर नए विद्यार्थी को किसी भी रूप में प्रताड़ित करने के मानसिक ढांचे के स्रोत क्या हैं! क्या इसके पीछे किसी नवागंतुक विद्यार्थी के मनोबल को तोड़ देने की मंशा काम करती है? आपसी परिचय या सहजता के नाम पर किसी विद्यार्थी को इस हद तक प्रताड़ित करना कि वह उसके लिए जानलेवा साबित हो, क्या एक सामंती कुंठा का परिचायक नहीं है? अगर परिचय के नाम पर यातना देने के चलन को आपस में सहज होने के लिए सिर्फ मनोविनोद के रूप में देखा-जाना जाता है, तो क्या यह एक आपराधिक तरीका नहीं है, जिसमें कालेज में आए एक नए विद्यार्थी के मन पर गहरी चोट पहुंचती है, वह खुद को अपमानित महसूस करता है, उसकी पढ़ाई बाधित हो सकती है? इस क्रम में शारीरिक और मानसिक यातना दिए जाने की वजह से किसी विद्यार्थी की जान जाने की घटनाएं अक्सर व्यापक चिंता का कारण बनती रही हैं और इस पर हर हाल में रोक लगनी चाहिए।

डॉ. कुँवर राज अस्थाना

मंत्री के पति के 'शर्मनाक बोल' से सियासी घमासान

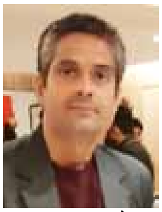

शंभू नाथ गौतम
वरिष्ठ पत्रकार

उत्तराखंड सरकार में महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल साहू के एक बयान ने उत्तराखंड से लेकर बिहार तक सियासी भूचाल खड़ा कर दिया है। अल्मोड़ा में दिए गए बयान में गिरधारी लाल साहू ने कहा था कि "अगर यहां शादी नहीं हो पा रही है तो बिहार से लड़की ले आएंगे, वहां 20-25 हजार रुपये में मिल जाएगी", जिसके बाद यह मामला सिर्फ एक व्यक्तिगत टिप्पणी न रहकर दो राज्यों की राजनीति का बड़ा विवाद बन गया। बिहार में राजद और कांग्रेस ने इसे महिलाओं के अपमान से जोड़ते हुए भाजपा पर तीखा हमला बोला, वहीं एनडीए के भीतर भी असहजता साफ नजर आई। जदयू और हम जैसे भाजपा के सहयोगी दलों ने भी बयान को शर्मनाक बताते हुए कार्रवाई की मांग की है। इस विवाद ने जहां बिहार की राजनीति को गरमा दिया है, वहीं उत्तराखंड में भी धामी सरकार और सत्तारूढ़ भाजपा की छवि को नुकसान पहुंचा है। विपक्ष इसे सत्ता की संवेदनहीनता का उदाहरण बता रहा है, जबकि सहयोगी दलों की आपत्ति ने इस मुद्दे को भाजपा के लिए और ज्यादा राजनीतिक चुनौती बना दिया है।

उत्तराखंड सरकार में महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल साहू के एक बयान ने ऐसी सियासी हलचल मचा दी है, जो अब केवल एक राज्य या एक दल तक सीमित नहीं रह गई है। अल्मोड़ा में सार्वजनिक रूप से दिए गए उनके कथित बयान "अगर यहां शादी नहीं हो पा रही है तो हम बिहार से लड़की ले आएंगे, वहां 20-25 हजार रुपये में मिल जाएगी" ने देखते ही देखते उत्तराखंड से लेकर बिहार तक राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया। यह टिप्पणी न सिर्फ महिलाओं की गरिमा और सम्मान पर सवाल उठाती है, बल्कि सामाजिक संवेदनशीलता, राजनीतिक जिम्मेदारी और सत्ता से जुड़े लोगों की सोच पर भी गहरी बहस को जन्म दे गई। बयान सामने आते ही बिहार की राजनीति में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली। राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस ने इसे बिहार की महिलाओं का अपमान बताते हुए भाजपा पर जोरदार हमला बोला। विपक्षी नेताओं का कहना है कि यह टिप्पणी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि उस राजनीतिक सोच का प्रतिबिंब है, जिसमें महिलाओं को वस्तु के रूप में देखा जाता है। राजद ने इसे बिहार की अस्मिता और महिलाओं के स्वाभिमान पर सीधा हमला करार दिया, जबकि कांग्रेस ने कहा कि सत्ता से जुड़े लोग अगर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो समाज में गलत संदेश जाएगा। बिहार में इस मुद्दे को लेकर प्रेस वार्ताएं, सोशल मीडिया अभियान और तीखे राजनीतिक बयान सामने आए, जिससे राज्य का राजनीतिक तापमान अचानक बढ़ गया। मामले की गंभीरता इस बात से और बढ़ गई कि इस पर सिर्फ विपक्ष ही नहीं, बल्कि भाजपा के सहयोगी दलों ने भी आपत्ति जताई।

एनडीए में शामिल जनता दल (यूनाइटेड) और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने बयान को दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक बताते हुए स्पष्ट रूप से इसकी निंदा की। जदयू नेताओं ने कहा कि महिलाओं को लेकर इस तरह की टिप्पणी किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं हो सकती, चाहे वह किसी भी दल या विचारधारा से जुड़ा व्यक्ति क्यों न हो। हम पार्टी ने भी बयान से खुद को अलग करते हुए कार्रवाई की मांग की। सहयोगी दलों की यह प्रतिक्रिया भाजपा के लिए असहज स्थिति पैदा करने वाली साबित हुई, क्योंकि आमतौर पर गठबंधन के भीतर ऐसे मामलों पर खुलकर विरोध कम ही देखने को मिलता है। उत्तराखंड में भी इस बयान ने राजनीतिक हलचल तेज कर दी है। विपक्षी दल कांग्रेस ने इसे धामी सरकार की संवेदनहीनता से जोड़ते हुए सरकार पर हमला बोला। साहू के विवादित बयान को लेकर गुरुवार को देहरादून और अल्मोड़ा में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। देहरादून में महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मंत्री के आवास का घेराव करने की कोशिश की, जहां पुलिस ने बैरिकेडिंग कर उन्हें रोक लिया। इस दौरान नारेबाजी, पुतला दहन और प्रतीकात्मक विरोध देखने को मिला। इस बयान से आक्रोशित उत्तराखंड प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने कहा- इस तरह की सोच मानव तस्करी, बाल विवाह, महिला शोषण और लैंगिक अपराध जैसी सामाजिक बुराइयों को सामान्य बनाने का काम करती है, मंत्री के पति ने उत्तराखंड का नाम खराब करने का काम किया है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि जिस राज्य में महिला एवं बाल विकास जैसा महत्वपूर्ण विभाग संभालने वाली मंत्री हैं, वहां उनके परिवार से जुड़े व्यक्ति का ऐसा बयान सरकार की सोच पर सवाल खड़े करता है। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से इस मामले में स्पष्ट रुख अपनाने और उचित कार्रवाई करने की मांग की है। विपक्ष का आरोप है कि अगर सत्ता पक्ष इस तरह की टिप्पणियों पर चुप्पी साधे रहता है, तो यह महिलाओं के सम्मान के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता पर गंभीर सवाल खड़े करेगा। इस पूरे विवाद ने धामी सरकार को भी असहज स्थिति में ला खड़ा किया है। एक ओर सरकार महिला सशक्तिकरण, बाल कल्याण और सामाजिक सुधारों की बात करती रही है, वहीं दूसरी ओर मंत्री के पति के बयान ने उन दावों को कमजोर किया है। यह मामला सरकार के लिए इसलिए भी संवेदनशील है क्योंकि उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य में सरकार और सत्ता से जुड़े लोगों की हर टिप्पणी का असर व्यापक होता है। सोशल मीडिया पर यह मुद्दा तेजी से वायरल हुआ, जहां बड़ी संख्या में लोगों ने बयान की निंदा की और कार्रवाई की मांग की।

गिरधारी लाल साहू के बयान पर भाजपा में भी दिखाई दी असहजता

भाजपा के भीतर भी इस बयान को लेकर असहजता देखी जा रही है। पार्टी के कई नेताओं ने निजी बातचीत में इसे अनुचित और गैर-जिम्मेदाराना बताया है, हालांकि सार्वजनिक रूप से पार्टी ने अब तक संतुलित प्रतिक्रिया देने की कोशिश की है। भाजपा के सामने चुनौती यह है कि वह एक तरफ महिला सम्मान और सामाजिक मूल्यों की बात करती है, वहीं दूसरी तरफ इस तरह के विवाद उसके राजनीतिक संदेश को कमजोर कर सकते हैं। बिहार में जहां भाजपा पहले

एनडीए के सहयोगी दलों ने भी मंत्री के पति के बयान की कड़ी निंदा की

उत्तराखंड सरकार में महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल साहू के बयान को लेकर विपक्षी दल राजद और कांग्रेस के अलावा एनडीए के साथी दलों जदयू और हम ने भी भाजपा नेता पर कार्रवाई की मांग की है। हम के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि अगर कीमत लगाने की बात है तो बहुत निंदनीय है। शादी खुशी से होती है। अगर उसे खरीदने की बात कर रहे हैं, तो बहुत गलत है। उन पर कार्रवाई होनी चाहिए और क्षमा मांगने की बात होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सामान्य तौर पर हर राज्य में लोग एक-दूसरे राज्य में शादी करते हैं, लेकिन अगर कीमत लगाने की बात है तो यह निंदनीय है। शादी, कीमत से नहीं बल्कि पारस्परिक सौहार्द से होती है। बिहार सरकार में मंत्री दिलीप जायसवाल ने उत्तराखंड की मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल साहू के बयान पर कहा कि हम इसकी भर्त्सना करते हैं। इस तरह की भाषा का उपयोग कभी नहीं करना चाहिए। इस टिप्पणी के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। बड़ी संख्या में लोग वीडियो को साझा करते हुए साहू की मानसिकता पर सवाल उठा रहे हैं और इसे महिलाओं के सम्मान के खिलाफ बता रहे हैं। बिहार राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष अप्सरा ने इस मामले को अत्यंत गंभीर बताया है। आयोग ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को औपचारिक पत्र लिखकर त्वरित कार्रवाई की मांग की है। आयोग का कहना है कि ये टिप्पणी न केवल अपमानजनक है, बल्कि सामाजिक ताने-बाने के लिए भी घातक है। आयोग ने कहा कि महिलाओं के सम्मान से जुड़ी किसी भी लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। महिला आयोग ने चिंता व्यक्त की है कि जिस परिवार की सदस्य स्वयं श्महिला सशक्तिकरणश विभाग की मंत्री हों, उसी परिवार से ऐसी सोच सामने आना दुर्भाग्यपूर्ण है। आयोग ने कहा कि सार्वजनिक जीवन में रहने वाले लोगों के परिजनों को भी शब्दों की मर्यादा का पालन करना चाहिए। आयोग ने मंत्री के पति से सार्वजनिक रूप से माफी और आधिकारिक स्पष्टीकरण सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। वहीं बिहार के सहरसा से विधायक और इंजीनियर इंद्रजीत प्रसाद गुप्ता (आईपी गुप्ता) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म श्एक्सश पर गिरधारी लाल साहू के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि बिहार की माताओं-बहनों पर अमर्यादित टिप्पणी करने वाले को बिहार की धरती पर लाकर सबक सिखाना जरूरी है। विधायक ने गिरधारी लाल साहू को पकड़कर बिहार लाने वाले के लिए 10 लाख रुपए के इनाम की घोषणा कर इस विवाद को और गरमा दिया है। उन्होंने लिखा, बिहार की महिलाओं पर अमर्यादित टिप्पणी करने वाले उत्तराखंड के नेता को बिहार पकड़ कर लाने वाले व्यक्ति को दूंगा 10 लाख रुपया इनाम।

से ही सामाजिक न्याय और महिला सम्मान जैसे मुद्दों पर विपक्ष के निशाने पर रहती है, वहां इस बयान ने विपक्ष को नया हथियार दे दिया है।
बिहार की राजनीति में यह मामला इसलिए भी अहम बन गया है क्योंकि राज्य में जाति, सामाजिक सम्मान और महिलाओं की सुरक्षा जैसे मुद्दे बेहद संवेदनशील माने जाते हैं। विपक्षी दलों ने इसे आगामी राजनीतिक लड़ाइयों से जोड़ते हुए भाजपा और एनडीए को घेरने की रणनीति बनाई है। उनका कहना है कि इस बयान ने यह साबित कर दिया है कि भाजपा और उससे जुड़े लोग महिलाओं के प्रति कितनी असंवेदनशील सोच रखते हैं। वहीं, एनडीए के सहयोगी दलों की आपत्ति ने यह संकेत भी दिया है कि गठबंधन के भीतर इस मुद्दे पर एक राय नहीं है।
उत्तराखंड में भी यह विवाद लंबे समय तक राजनीतिक चर्चा का विषय बने रहने की संभावना है। राज्य में पहले ही कई मुद्दों पर विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश में लगा हुआ है, और यह बयान उसके लिए एक बड़ा मौका बनकर सामने आया है। कांग्रेस इसे महिला सम्मान और सामाजिक मूल्यों से जोड़कर सरकार पर लगातार दबाव बनाने की रणनीति अपना रही है। वहीं, सत्तारूढ़ भाजपा के लिए यह मामला इसलिए भी चुनौतीपूर्ण है क्योंकि पार्टी को अपनी छवि बचाने के साथ-साथ सहयोगी दलों और राष्ट्रीय स्तर पर हो रही आलोचना का भी सामना करना पड़ रहा है। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि सत्ता से जुड़े लोगों को सार्वजनिक मंचों पर बोलते समय कितनी जिम्मेदारी और संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। एक बयान, जो शायद स्थानीय स्तर पर दिया गया था, उसने दो राज्यों की राजनीति को हिला दिया और राष्ट्रीय स्तर पर बहस का मुद्दा बन गया। बिहार और उत्तराखंड दोनों ही राज्यों में यह मामला अब सिर्फ राजनीतिक विवाद नहीं, बल्कि सामाजिक चेतना और महिला सम्मान से जुड़ी बहस का रूप ले चुका है। आने वाले दिनों में यह देखना अहम होगा कि भाजपा और धामी सरकार इस पर क्या रुख अपनाती है और क्या कोई ठोस कार्रवाई या स्पष्टीकरण सामने आता है, या फिर यह मुद्दा सियासी आरोप-प्रत्यारोप के बीच और गहराता चला जाता है। वहीं दूसरी ओर इस मामले में जब तूल पकड़ा तब मंत्री के पति गिरधारी लाल साहू ने क्षमा मांगी है।
मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल साहू ने वीडियो जारी कर कहा कि सोमेश्वर विधानसभा के दौलाघट क्षेत्र में आयोजित माताओं-बहनों और बुजुर्गों के स्वागत समारोह में वह मंडल अध्यक्ष गणेश जलाल के आमंत्रण पर शामिल हुए थे। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में एक मित्र की शादी का जिक्र हास्य के रूप में किया था, लेकिन कांग्रेस और विरोधियों ने उसे जानबूझकर तोड़-मरोड़कर समाज के सामने गलत तरीके से पेश किया है, जो पूरी तरह निराधार है। साहू ने कहा कि बेटियों के सम्मान को लेकर उनकी सोच और कामकाज किसी से छिपा नहीं है। उन्होंने दावा किया कि वह हर वर्ष बरेली में रामलीला के माध्यम से 101 निर्धन बेटियों की शादी कराते हैं और लंबे समय से अपनी श्रद्धा व सामर्थ्य के अनुसार इन विवाहों में सहयोग करते आ रहे हैं। उनके अनुसार, यह उनका निजी सामाजिक दायित्व है, जिसे वे निरंतर निभाते रहे हैं। गिरधारी लाल साहू ने कहा कि वह सोमेश्वर विधानसभा ही नहीं, बल्कि प्रदेश और देश की सभी बेटियों का देवी के समान सम्मान करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस उनके बयान को गलत तरीके से पेश कर राजनीतिक लाभ लेना चाहती है।

मिल्टन और वेस्ट वॉरियर संस्था की साझेदारी से देहरादून में कचरा प्रबंधन को मजबूती

हैमिल्टन हाउसवेयर प्राइवेट लिमिटेड (मिल्टन) पिछले तीन वर्षों से देहरादून और आसपास के क्षेत्रों में कचरा प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए वेस्ट वॉरियर संस्था के साथ मिलकर काम कर रही है। इस सहयोग के तहत मिल्टन, वेस्ट वॉरियर संस्था के मटेरियल रिकवरी सेंटर (MRF) को सहयोग प्रदान कर रहा है, जहां घरों और संस्थानों से आने वाले कचरे को वैज्ञानिक तरीके से अलग-अलग किया जाता है और पुनर्चक्रण के लिए भेजा जाता है। पिछले तीन वर्षों में इस परियोजना के माध्यम से कुल 714.44 टन कचरा एकत्र किया गया, जिसमें से 691.74 टन कचरा रीसाइक्लिंग के लिए अधिकृत इकाइयों तक भेजा गया। इससे लैंडफिल में जाने वाले कचरे में काफी कमी आई है और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिला है।

मिल्टन ने सिर्फ बुनियादी ढांचे और संचालन में ही नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर काम करने वाले सफाई साथियों (ग्रीन वर्कर्स) को सशक्त बनाने पर भी ध्यान दिया है। हाल ही में मटेरियल रिकवरी सेंटर में बेसिक साक्षरता और वित्तीय साक्षरता से जुड़े प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए गए, ताकि सफाई साथियों को आत्मनिर्भर बनाया जा सके।

वर्तमान में इस परियोजना के अंतर्गत 12 सफाई साथी और वेस्ट वॉरियर संस्था की 3 सदस्यीय टीम मिल्टन के सहयोग से कार्य कर रही है। यह पहल पर्यावरण की रक्षा के साथ-साथ स्थानीय लोगों को सम्मानजनक आजीविका भी प्रदान कर रही है।

मिल्टन का वेस्ट वॉरियर संस्था को दिया जा रहा निरंतर सहयोग उत्तराखंड में पर्यावरण संरक्षण, सर्कुलर इकॉनॉमी और समावेशी विकास के प्रति कंपनी की दीर्घकालिक प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

उत्तराखंड के लिए विकास और विश्वास का नया साल

नए साल 2026 की दस्तक के साथ ही देवभूमि उत्तराखंड में उम्मीदों की नई किरणें दिखाई देने लगी। पहाड़ से मैदान तक, गांव से राजधानी देहरादून तक, यह साल केवल कैलेंडर का बदलाव नहीं बल्कि धामी सरकार के लिए अपने कामकाज को निर्णायक मोड़ तक पहुंचाने का अवसर भी लेकर आया है। 2027 में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव से पहले यह वर्ष सरकार के लिए 'परिणाम दिखाने का साल' माना जा रहा है, जहां विकास योजनाओं की रफ्तार, जनविश्वास की मजबूती और शासन की दिशा जनता के सामने परखी जाएगी। दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे जैसे बहुप्रतीक्षित प्रोजेक्ट के शुभारंभ से लेकर बुनियादी ढांचे, कनेक्टिविटी, रोजगार और तीर्थाटन-पर्यटन को नई गति देने वाली योजनाओं तक, 2026 धामी सरकार के विजन को जमीन पर उतारने का साल है। एक ओर सरकार विकास के नए अध्याय लिखने की तैयारी में है, तो दूसरी ओर जनता की उम्मीदें भी पहले से कहीं अधिक बढ़ चुकी हैं। ऐसे में यह नया साल उत्तराखंड के लिए सिर्फ आगे बढ़ने का रास्ता नहीं, बल्कि विश्वास और भविष्य की राजनीति की नींव मजबूत करने का वर्ष बनता नजर आ रहा है।

साल 2026 का उत्तराखंड में उत्साह, उम्मीद और विश्वास के साथ जोरदार स्वागत हुआ है। देवभूमि के पहाड़ों से लेकर मैदानों तक नया साल केवल तारीख बदलने का अवसर नहीं बना, बल्कि आने वाले समय की दिशा और दशा तय करने वाला पड़ाव बनकर सामने आया है। देश, विदेश से नए साल का स्वागत करने के लिए हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। राजधानी देहरादून, मसूरी, नैनीताल ऋषिकेश और हरिद्वार में लोगों ने साल 2026 का जोरदार स्वागत किया। यह नया साल धामी सरकार के लिए भी कई बड़ी विकास योजनाएं और राजनीति दृष्टि से खास है। बीते वर्षों में जिन विकास योजनाओं की नींव रखी गई थी, 2026 वह साल माना जा रहा है जब उनके ठोस परिणाम जनता के सामने दिखाई देंगे। यही कारण है कि यह वर्ष धामी सरकार के लिए प्रशासनिक, राजनीतिक और जनविश्वास, तीनों दृष्टियों से बेहद अहम माना जा रहा है, खासकर तब जब 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव अब ज्यादा दूर नहीं रह गए हैं। दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे का शुभारंभ 2026 की सबसे बड़ी उपलब्धियों में गिना जा रहा है। इस परियोजना के शुरू होने से न केवल राजधानी देहरादून की कनेक्टिविटी देश की राजधानी दिल्ली से और बेहतर होगी, बल्कि उद्योग, निवेश और पर्यटन को भी नई गति मिलेगी। सरकार का मानना है कि बेहतर सड़क और परिवहन नेटवर्क से पहाड़ी क्षेत्रों में भी विकास की रफ्तार तेज होगी और पलायन जैसी समस्याओं पर प्रभावी रोक लगेगी। इसके साथ ही चारधाम ऑल वेदर रोड, सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क नेटवर्क, रेल परियोजनाओं और हेली सेवाओं के विस्तार पर भी सरकार का विशेष फोकस बना हुआ है। पर्यटन उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है और 2026 में इसे नई ऊंचाइयों पर ले जाने की तैयारी है। शीतकालीन चारधाम यात्रा, धार्मिक पर्यटन के साथ-साथ एडवेंचर, ईको और होम-स्टे पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई नई योजनाएं लागू की जा रही हैं। सरकार का दावा है कि इससे स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। इसके साथ ही केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री सहित प्रमुख धार्मिक स्थलों पर सुविधाओं का विस्तार भी तेज गति से किया जा रहा है। राजनीतिक दृष्टि से भी 2026 बेहद अहम है। 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले यह साल धामी सरकार के लिए अपने कार्यकाल की उपलब्धियों को जनता के सामने रखने का आखिरी पूरा मौका है। ऐसे में सरकार विकास कार्यों की रफ्तार बढ़ाने के साथ-साथ कानून-व्यवस्था, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण और सुशासन के मुद्दों पर भी विशेष ध्यान दे रही है। समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून और सख्त प्रशासनिक फैसलों के जरिए सरकार पहले ही अपनी मंशा साफ कर चुकी है कि वह निर्णायक और सख्त फैसलों से पीछे नहीं हटेगी। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी 2026 को सुधार और विस्तार का वर्ष माना जा रहा है। सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में बुनियादी सुविधाओं को बेहतर करने, डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने और स्वास्थ्य सेवाओं को दूर-दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए नई योजनाएं अमल में लाई जा रही हैं। टेलीमेडिसिन, मेडिकल कॉलेजों का विस्तार और जिला अस्पतालों के आधुनिकीकरण पर भी सरकार का फोकस है, ताकि आम

लोगों को बेहतर इलाज के लिए बड़े शहरों की ओर न जाना पड़े। आपदा प्रबंधन उत्तराखंड के लिए हमेशा एक संवेदनशील विषय रहा है। 2026 में सरकार का लक्ष्य आपदा पूर्व चेतावनी प्रणाली, राहत और पुनर्वास तंत्र को और मजबूत करना है। राज्यपाल और मुख्यमंत्री दोनों ने अपने संदेशों में इस बात पर जोर दिया कि प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए वैज्ञानिक, तकनीकी और सामुदायिक स्तर पर तैयारी को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके लिए केंद्र सरकार के सहयोग से कई नई परियोजनाएं भी आगे बढ़ाई जा रही हैं। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) गुरमीत सिंह ने नए साल के अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि 2026 उत्तराखंड के लिए विकास, स्थिरता और सामाजिक समरसता का वर्ष बने। उन्होंने विश्वास जताया कि राज्य सरकार और जनता के साझा प्रयासों से उत्तराखंड न केवल आर्थिक रूप से मजबूत होगा, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में भी नई मिसाल कायम करेगा।

राज्यपाल ने युवाओं, महिलाओं और सैनिक परिवारों के योगदान को विशेष रूप से रेखांकित करते हुए कहा कि देवभूमि की ताकत उसकी अनुशासित, परिश्रमी और जागरूक जनता है, जो हर चुनौती में राज्य के साथ खड़ी रहती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी नए साल पर प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए इसे "विकास और विश्वास का नया अध्याय" बताया।

मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि 2026 उत्तराखंड के लिए निर्णायक वर्ष है, जब सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाएं धरातल पर पूरी ताकत के साथ दिखाई देंगी। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार का लक्ष्य केवल योजनाओं की घोषणा नहीं, बल्कि समयबद्ध क्रियान्वयन और उसका सीधा लाभ आम जनता तक पहुंचाना है। हमारा लक्ष्य स्पष्ट है विकास की धारा अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, चाहे वह दूरस्थ पहाड़ का गांव हो या सीमांत क्षेत्र। युवा सशक्त हों, मातृशक्ति आत्मनिर्भर बने, पर्यावरण संरक्षण के साथ पर्यटन, कृषि और उद्योग को संतुलित गति मिले। इसी दिशा में निरंतर कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, रोजगार, पर्यटन और सुरक्षा के क्षेत्र में यह साल मील का पत्थर साबित होगा। 2026 उत्तराखंड के लिए उम्मीदों, योजनाओं और निर्णायक कदमों का साल बनकर उभरा है। जनता की निगाहें सरकार के वादों और दावों पर टिकी हैं, वहीं सरकार इसे विश्वास जीतने के अवसर के रूप में देख रही है। राज्यपाल गुरमीत सिंह के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में यह साल प्रदेश को विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा या नहीं, इसका फैसला आने वाला समय करेगा। लेकिन फिलहाल नए साल की शुरुआत उत्तराखंड में सकारात्मक माहौल, बढ़ती उम्मीदों और मजबूत इरादों के साथ हुई है, जो यह संकेत देती है कि देवभूमि 2026 में नए सपनों और नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ने को तैयार है।

सीएम धामी ने 88.84 करोड़ धनराशि विकास योजनाओं के लिए स्वीकृत की

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में विभिन्न विकास योजनाओं के लिए कुल 88.84 करोड़ की धनराशि के अनुमोदन को स्वीकृति प्रदान की है। इस क्रम में मुख्यमंत्री ने शारदा घाट परियोजना के अंतर्गत सिटी ड्रेनेज प्लान फेज-1 के निर्माण कार्य हेतु 65.65 करोड़ की योजना को मंजूरी दी है। इस परियोजना से शहरी क्षेत्रों में जल निकासी की समस्या के समाधान और बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा मुख्यमंत्री द्वारा जनपद देहरादून के अंतर्गत जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर स्टेट गेस्ट हाउस के निर्माण के लिए 4.46 करोड़ की धनराशि स्वीकृत किए जाने का अनुमोदन भी प्रदान किया गया है। इससे राज्य में आने वाले विशिष्ट अतिथियों एवं सरकारी कार्यों के संचालन में सुविधा मिलेगी। आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में भी मुख्यमंत्री ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। विभिन्न जनपदों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर 30 प्रतिशत से 70 प्रतिशत तक क्षतिग्रस्त 225 पटवारी चौकियों तथा

राज्यपाल ने प्रदेशवासियों को नव वर्ष 2026 की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी

राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से नि) ने प्रदेशवासियों को नव वर्ष 2026 की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में उन्होंने नव वर्ष के अवसर पर प्रदेश के विकास के साथ-साथ सभी नागरिकों के अच्छे स्वास्थ्य, सुख, शांति और समृद्धि की कामना की है। उन्होंने कहा कि सभी लोग नई सोच, नई ऊर्जा और सकारात्मक भावना के साथ मिलकर 'देवभूमि' उत्तराखण्ड के विकास में योगदान दें।

राज्यपाल ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) आज सभी क्षेत्रों में बदलाव की नई शक्ति बनकर उभरी है। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, प्रशासन और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में एआई के उपयोग से कार्य अधिक सरल, तेज और प्रभावी हो सकता है। उन्होंने कहा कि एआई का सही और जिम्मेदार उपयोग प्रदेश के संतुलित विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। राज्यपाल ने युवाओं से आहवान किया कि वे तकनीक और नवाचार को अपनाकर उत्तराखण्ड को प्रगति के नए शिखर तक ले जाएं।

राज्यपाल ने कहा कि वर्ष 2025 उत्तराखण्ड के लिए विकास और सामूहिक प्रयासों का महत्वपूर्ण वर्ष रहा है। उन्होंने कहा कि देवभूमि की वास्तविक शक्ति उसके नागरिक हैं, विशेष रूप से युवा, महिलाएं, किसान और छात्र जो आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं।

राज्यपाल ने कहा कि यह समय है जब हम सभी मिलकर 'विकसित उत्तराखण्ड' और 'विकसित भारत' के लक्ष्य को पूरा करने के लिए एकजुट होकर काम करें। उन्होंने विश्वास जताया कि प्रदेशवासियों की मेहनत और सहयोग से उत्तराखण्ड एक उज्ज्वल और स्वर्णिम भविष्य की ओर आगे बढ़ेगा।

मुख्यमंत्री को विभिन्न क्षेत्रों के लोगों ने दी नववर्ष की शुभकामनाएं

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री आवास पर मंत्रीगणों, विधायकों, जनप्रतिनिधियों, शासन-प्रशासन एवं पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों-कर्मचारियों तथा प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों ने शिष्टाचार भेंट कर उन्हें नववर्ष की शुभकामनाएँ दीं। आई.टी.बी.पी. सहित केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों व संगठनों के उच्चाधिकारियों ने भी मुख्यमंत्री से भेंट कर उन्हें नववर्ष की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री श्री धामी ने सभी आगंतुकों का हार्दिक स्वागत करते हुए शुभकामनाओं के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि नया वर्ष नई ऊर्जा, नए संकल्प और नए अवसरों का प्रतीक होता है, जो हमें समाज और राज्य की सेवा के प्रति और अधिक दृढ़ संकल्पित करता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2026 उत्तराखंड की विकास यात्रा में एक महत्वपूर्ण वर्ष सिद्ध होगा। इस वर्ष राज्य सरकार सुशासन, जनकल्याण और आत्मनिर्भरता के लक्ष्यों की दिशा में और अधिक सशक्त कदम बढ़ाएगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि जन-जन तक विकास योजनाओं का लाभ पहुँचाना, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित करना, महिलाओं को सशक्त बनाना, शिक्षा और स्वास्थ्य सहित बुनियादी सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण तथा प्रदेश की प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण सरकार की प्रमुख प्राथमिकताएँ हैं। देवभूमि उत्तराखंड के धार्मिक स्वरूप को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सरकार कृतसंकल्प है। मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि शासन-प्रशासन और जनता के सहयोग से उत्तराखंड को देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में स्थान दिलाने के संकल्प को साकार करने की दिशा में यह वर्ष एक महत्वपूर्ण पड़ाव सिद्ध होगा।

मुख्यमंत्री श्री धामी ने सभी लोगों से एकजुट होकर राज्य के विकास में जुटे रहने का आह्वान किया। उन्होंने प्रदेश के नागरिकों के सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना करते हुए कहा कि नया वर्ष सबके जीवन में खुशियाँ, सफलता और नई संभावनाएँ लेकर आए।

70 प्रतिशत से अधिक क्षतिग्रस्त 37 पटवारी चौकियों के पुनर्निर्माण एवं निर्माण कार्य हेतु आपदा राहत निधि से 15 करोड़ की धनराशि स्वीकृत किए जाने का अनुमोदन दिया गया है। इससे राजस्व व्यवस्था को सुदृढ़ करने के साथ-साथ आपदा प्रभावित क्षेत्रों में प्रशासनिक ढांचे को फिर से मजबूत किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री ने जनपद चंपावत के अंतर्गत सहायक नदी/धारा उपचार (कालसन भोलेश्वर) परियोजना के तहत समग्र जल संरक्षण, जल संवर्धन एवं मृदा संरक्षण से संबंधित कार्यों के लिए 3.39 करोड़ की योजना को जलागम प्रबंधन के अंतर्गत स्वीकृति प्रदान की है। इस योजना से क्षेत्र में जल स्रोतों के संरक्षण और पर्यावरण संतुलन को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही राजस्व परिषद द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रस्ताव के क्रम में जिला कार्यालय, देहरादून के लिए निष्प्रयोज्य वाहनों के स्थान पर तीन नए बोलेरो वाहनों की खरीद को भी मुख्यमंत्री ने मंजूरी दी है। प्रत्येक वाहन की लागत 10 लाख निर्धारित की गई है। इन स्वीकृतियों के माध्यम से राज्य सरकार ने स्पष्ट संकेत दिया है कि बुनियादी ढांचे, आपदा प्रबंधन, जल संरक्षण और प्रशासनिक सुदृढ़ीकरण को लेकर सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ रही है।

धामी सरकार का 'जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार' अभियान आम लोगों से सीधे जुड़ा

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दूरदर्शी नेतृत्व में उत्तराखण्ड सरकार द्वारा संचालित "जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार" कार्यक्रम प्रदेश में सुशासन, जवाबदेही और त्वरित समाधान का मजबूत प्रतीक बनकर उभरा है। यह अभियान केवल एक सरकारी पहल नहीं, बल्कि शासन की कार्यसंस्कृति में आए सकारात्मक बदलाव का जीवंत उदाहरण बन चुका है। इस कार्यक्रम ने सरकार और आम नागरिक के बीच वर्षों से चली आ रही दूरी को कम करते हुए प्रशासन को सीधे जनता के द्वार तक पहुंचाया है। 2 जनवरी 2026 को जारी कार्यक्रम की दैनिक प्रगति रिपोर्ट इस बात की स्पष्ट पुष्टि करती है कि राज्य सरकार अब योजनाओं को कागजों तक सीमित रखने के बजाय उन्हें धरातल पर प्रभावी ढंग से लागू कर रही है। प्रदेश के सभी 13 जनपदों में अब तक कुल 204 जनसेवा शिविर आयोजित किए जा चुके हैं, जिनमें 1 लाख 35 हजार 194 से अधिक नागरिकों ने प्रत्यक्ष रूप से सहभागिता की। इतनी बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी यह दर्शाती है कि यह अभियान जनता की वास्तविक जरूरतों से जुड़ा हुआ है और लोगों ने इसे विश्वास के साथ अपनाया है। इन शिविरों के माध्यम से शासन-प्रशासन पहली बार संगठित रूप से सीधे जनता के बीच पहुंचा, जिससे ग्रामीण, पर्वतीय और दूरस्थ क्षेत्रों के नागरिकों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए जिला या तहसील मुख्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़े। लोगों को अपने ही क्षेत्र में प्रशासनिक अधिकारियों से सीधा संवाद और समाधान का अवसर मिला, जिससे समय, धन और श्रम तीनों की बचत हुई। कार्यक्रम के दौरान कुल 17 हजार 747 शिकायतें और प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, जिनमें से 12 हजार 776 मामलों का मौके पर ही अथवा

त्वरित कार्रवाई के माध्यम से निस्तारण कर दिया गया। यह आंकड़ा बताता है कि लगभग तीन-चौथाई समस्याओं का समाधान तुरंत किया गया, जो प्रशासनिक दक्षता, निर्णय क्षमता और जवाबदेही का मजबूत प्रमाण है। शेष मामलों को भी समयबद्ध कार्ययोजना के तहत संबंधित विभागों को सौंपते हुए नियमित निगरानी में रखा गया है, ताकि कोई भी शिकायत लंबित न रहे। जनसेवा शिविरों में आय, जाति, निवास, सामाजिक श्रेणी सहित अन्य आवश्यक प्रमाण पत्रों से संबंधित कुल 19 हजार 734 आवेदन प्राप्त हुए। इससे यह स्पष्ट है कि अब नागरिकों को मूलभूत सेवाओं के लिए अनावश्यक देरी या जटिल औपचारिकताओं का सामना नहीं करना पड़ रहा है। सेवाओं को जनता के नजदीक लाने की यह पहल विशेष रूप से गरीब, वंचित और दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो रही है। इसके अतिरिक्त, विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत कुल 77 हजार 203 नागरिकों को प्रत्यक्ष लाभ प्रदान किया गया। यह संख्या इस बात का ठोस प्रमाण है कि योजनाएं अब केवल घोषणाओं तक सीमित नहीं रह गई हैं, बल्कि पात्र लाभार्थियों तक वास्तविक रूप से पहुंच रही हैं। सामाजिक सुरक्षा, पेंशन, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य कल्याणकारी योजनाओं का लाभ एक ही मंच पर उपलब्ध कराकर सरकार ने सुविधा, पारदर्शिता और विश्वास तीनों को सशक्त किया है। इस कार्यक्रम की सफलता के पीछे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के स्पष्ट, सख्त और परिणामोन्मुख निर्देशों की अहम भूमिका रही है। उन्होंने शुरुआत से ही यह सुनिश्चित किया कि अधिकारी जनता को कार्यालयों में बुलाने के बजाय स्वयं फील्ड में जाकर समस्याओं का समाधान करें। प्रत्येक शिविर में निर्णय लेने में सक्षम अधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य की गई और प्राथमिक स्तर पर ही शिकायतों के निस्तारण के निर्देश दिए गए। साथ ही लंबित मामलों की जिला व राज्य स्तर पर नियमित मॉनिटरिंग, कमजोर वर्गों, दिव्यांगों, बुजुर्गों और दूरस्थ क्षेत्रों के नागरिकों को प्राथमिकता तथा लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों की जवाबदेही तय करने से प्रशासनिक तंत्र अधिक संवेदनशील और सक्रिय बना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार उत्तराखण्ड में शासन की सोच को बदलने वाला अभियान है। लोकतंत्र तभी मजबूत होता है जब सरकार स्वयं जनता तक पहुंचे। इस कार्यक्रम के माध्यम से यह सुनिश्चित किया गया है कि अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति भी बिना किसी बाधा के सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ प्राप्त कर सके। यह केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि विश्वास, समाधान और संवेदनशीलता पर आधारित उत्तराखण्ड मॉडल ऑफ गुड गवर्नेंस है। उन्होंने यह भी कहा कि इस व्यापक अभियान से न केवल प्रशासन पर जनता का विश्वास बढ़ा है, बल्कि बिचौलियों और भ्रष्टाचार पर भी प्रभावी अंकुश लगा है। सरकार और जनता के बीच सीधा संवाद स्थापित होने से समस्याओं के त्वरित समाधान की संस्कृति विकसित हुई है और शासन की पारदर्शिता, विश्वसनीयता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार आज उत्तराखण्ड में सुशासन की नई पहचान बन चुका है और आने वाले समय में भी यह राज्य के विकास और जनकल्याण की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।

मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने नववर्ष के शुभ अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं

इस अवसर पर सचिवालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्य सचिव ने सचिवालय परिवार और पूरे प्रदेशवासियों को नववर्ष कर की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी एवं प्रदेशवासियों के सुख, समृद्ध, आनन्दमय एवं खुशहाल जीवन की कामना की।

सचिवालय परिसर में उपस्थित सभी अधिकारी-कर्मचारीगण ों को सम्बोधित करते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि यह सचिवालय राज्य की सर्वोच्च संस्था है। हम सभी इस संस्था के भागीदार हैं, इस राज्य की समस्त नीतियां और महत्त्वपूर्ण निर्णय इसी संस्था से निकलते हैं। इसलिए इस संस्था की गरिमा बनाए रखने और इसके उद्देश्यों को फलीभूत करने की जिम्मेदारी हम सभी की है। नववर्ष के अवसर पर हमें यह संकल्प लेना है कि इस संस्था की गरिमा और इसका स्टेटस सिर्फ उत्तराखण्ड ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों के लिए भी प्रेरणा बने। उन्होंने कहा कि हमें प्रदेश एवं प्रदेशवासियों की सेवा के लिए, उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए Whole of Government Approach अपनाते हुए Single Entity के रूप में कार्य करते हुए प्रदेशवासियों के सुख दुख में सहभागी बनना है।

इस अवसर पर अपर सचिव श्री नवनीत पाण्डेय, सचिवालय संघ के पदाधिकारी एवं सचिवालय के समस्त अधिकारी कर्मचारीगण उपस्थित थे।

हिंदी के लिए पूरे वर्ष सक्रिय रहे साहित्यकार श्रीगोपाल नारसन

डॉ. सविता वर्मा गजल

देवभूमि उत्तराखंड के साहित्यकार श्रीगोपाल नारसन सन 2025 में भी हिंदी के लिए सक्रिय रहे, साथ ही उनकी आध्यात्मिक सक्रियता भी बनी रही। उनकी हरदिन लिखी जा रही कविता ने जहां मन मोहे रखा वही नेपाल-भारत द्वारा संयुक्त साहित्य संगठन के माध्यम से विश्व हिंदी कविता प्रतियोगिता में श्रीगोपाल नारसन को सम्मान मिलना बड़ी उपलब्धि है। उनके द्वारा वर्तमान में उपभोक्ता कानून पर एक पुस्तक लाई जा रही है।

विविधताओं का शहर रुड़की उनकी पुस्तक सन 2023 में प्रकाशित हो चुकी है। अपने अभी तक के साहित्यिक जीवन मे 22 पुस्तकें लिख चुके श्रीगोपाल नारसन को हिंदी की अंतरराष्ट्रीय पुरातन संस्था विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ भागलपुर बिहार ने हिंदी साहित्य में विशेष सेवा, सारस्वत साधना व कलात्मक सोच के लिए रामधारी सिंह दिनकर सम्मान से विभूषित किया था। उन्हें न्यायमूर्ती राजेश टण्डन व न्यायमूर्ति यू सी ध्यानी ने मानवाधिकार संरक्षण रत्न सम्मान 2023 से भी विभूषित किया है। उत्तराखंड के साहित्यकार श्रीगोपाल नारसन की प्रकाशित पुस्तकों मे 'नया विकास', 'मीडिया को फांसी दो', 'खामोश हुआ जंगल', 'प्रवास', 'तिनका तिनका संघर्ष', 'पदचिन्ह', चैक पोस्ट, श्रीमद्भागवत गीता शिव परमात्मा उवाच, दादी जानकी, आबू तीर्थ महान, विविधताओं का शहर रुड़की, ईश्वरीय गुलदस्ता आदि शामिल है। उनके साहित्यिक योगदान पर भी 3 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है, जिनमे 'श्रीगोपाल नारसन और उनका साहित्य' व 'श्रीगोपाल नारसन का आध्यात्मिक चिंतन', 'श्रीगोपाल की आध्यात्म काव्यधारा' शामिल है। श्रीगोपाल नारसन के शब्दकोश में 'खाली समय' शब्द नहीं है, क्योंकि वे कभी खाली रहते ही नही। बड़े सवेरे 4 बजे उठकर रात्रि 11 बजे तक की उनकी दैनिक दिनचर्या में कभी कोई खाली समय नही होता। पीड़ित उपभोक्ताओं को न्याय दिलाने के लिए वकालत के क्षेत्र में सक्रिय श्रीगोपाल नारसन ब्रह्माकुमारीज के माध्यम से आध्यात्मिक सेवा कार्य भी करते है। इसके बाद जो भी समय उन्हें मिलता है, उस समय का सदुपयोग श्रीगोपाल नारसन साहित्य सृजन कर अपने जीवन को सार्थक बना रहे हैं। जीवन से जुड़े अनेक विषयों पर काव्य की रचना करना भी उनकी दिनचर्या में शामिल है। उन्हें डॉ आंबेडकर फैलोशिप सम्मान, विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ का सर्वोच्च 'भारत गौरव' सम्मान, भारत नेपाल साहित्यिक मैत्री सम्मान, मानसश्री सम्मान व हाल ही में मिला सृजन समन्वय सम्मान 2025 आदि शामिल है।

आज के समय मे जहां लोग एक-दूसरे से केवल स्वार्थसिद्धि हेतु ही बात करते हैं, वहीं वह हर सुबह अनेक माध्यमों से चाहे वह फेसबुक हो, मैसेंजर हो या फिर व्हाट्सएप,इंस्टाग्राम व टयूटर आदि पर ही निस्वार्थ परमात्मा से जुड़े प्रेरणादायक व परोपकार की भावना से ओतप्रोत आध्यात्मिक सन्देश मौलिकता के साथ भेजते है श्रीगोपाल नारसन, जो देवभूमि उत्तराखंड के अभियंता नगरी रुड़की के निवासी है और साथ साथ ही मुख्यमंत्री के प्रवक्ता भी रहे है। उनकी गिनती वरिष्ठ साहित्यकार के रूप में होती हैं। देश की आजादी के अमर शहीद जगदीश प्रसाद वत्स के भांजे श्रीगोपाल नारसन ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी प्रकोष्ठ द्वारा तीन दशक पूर्व संचालित किए गए चरित्र निर्माण शिविरों में सक्रिय भूमिका निभाई, साथ ही राजकीय महाविद्यालय देवबंद के छात्र संघ अध्यक्ष के रूप में उन्होंने अपनी राजनीतिक शुरुआत की। मां शारदे की अनुकम्पा से

श्रीगोपाल नारसन एक सरल व्यक्तित्व के धनी तो हैं ही साथ ही इनमें सादगी, विन्रमता, धैर्य, ईमानदारी, कर्मठता, अपनत्व की भावना भी कूट-कूट कर भरी हैं। श्रीगोपाल नारसन को उत्तराखंड की शान व साहित्य से लेकर धार्मिक, राजनीतिक आदि समस्त ज्ञान का भंडार व बहुमुखी प्रतिभा के धनी कहा जाए तो कोई अतिश्योक्ति न होगी।

व्यवसाय से उपभोक्ता राज्य आयोग के वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में विगत 35 वर्षो से उपभोक्ता जनजागरूकता के क्षेत्र में अपनी राष्ट्र व्यापी भूमिका वे निभा रहे है। श्रीगोपाल नारसन उपभोक्ता कानून की गहन जानकारी रखते हैं और आकाशवाणी, प्रिंट मीडिया के साथ ही जगह-जगह जाकर 'जागो ग्राहक जागो' की अलख जगाना उनकी नियमित कार्य शैली का हिस्सा है, ताकि लोग अपने उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूक होकर शोषण व उत्पीड़न से स्वयं को बचा सके।उनका दैनिक ट्रिब्यून में उपभोक्ता कानून पर नियमित कॉलम आता है।

अनेक शिक्षण संस्थान उन्हें अपने यहां अतिथि प्रवक्ता के रूप में आमंत्रित करते हैं, जिससे कानून की जानकारी स्कूल कॉलेज के छात्र व छात्राओं को आसानी से मिल सके।

वे निस्वार्थ भाव से कानून की सेवा करने के कारण ही विभिन्न शिक्षण संस्थाओं व विधिक सेवा प्राधिकारण के शिविरो में उपभोक्ता कानून विशेषज्ञ के रूप में जाने जाते हैं। जीवन से जुड़े अनेक विषयों पर काव्य की रचना करना उनकी सबसे बड़ी खूबी है। एक बेबाक वक्ता के रूप में टीवी चैनलों पर बहस करते हुए वे

बहुत ही संयमित, मर्यादित रूप से, सदव्यवहार के धनी श्रीगोपाल नारसन साफ गोई से अपनी बात को रखते हैं। कानफोड़ू टीवी डिबेट को वे अच्छा नही मानते। दूसरे का सम्मान करते हुए अपनी बात मजबूती से रखना उन्हें अच्छी तरह आता है।

पत्रकारिता के क्षेत्र में भी एक वरिष्ठ पत्रकार के रूप में उनकी गिनती होती है। देश विदेश की अनेक पत्र और पत्रिकाओं में उनके लेख आए दिन प्रकाशित होते रहे हैं। उन्हें अनेक सम्मानो से विभूषित किया जा चुका है। जिनमे डॉ आंबेडकर फैलोशिप सम्मान, विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ का सर्वोच्च 'भारत गौरव' सम्मान, भारत नेपाल साहित्यिक मैत्री सम्मान आदि शामिल है। श्री गोपाल नारसन वर्तमान में 'विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ भागलपुर, बिहार' के प्रतिकुलपति भी हैं। जो उनके हिंदी प्रेम व अथक परिश्रम का परिचायक हैं।

'अंतर्राष्ट्रीय सिद्धार्थ साहित्य कला' सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश द्वारा उनको अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार भी प्रदान किया गया हैं।

खेलों के क्षेत्र में भी उन्हें बचपन से ही रुचि रही है तथा विद्यार्थी जीवन से ही वे एक अच्छे खिलाड़ी रहे। श्रीगोपाल नारसन ने पांच किमी पैदल चाल में राज्य स्तर पर स्वर्ण पदक प्राप्त किया हुआ है। दौड़ व तैराकी में भी इनकी भागेदारी रही हैं। उत्तराखंड व पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक सक्रिय समाज सेवी के रूप में उनकी अच्छी खासी पहचान है। प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के मीडिया विंग के आजीवन सदस्य के रूप में वे रूहानियत की राह पर भी उतने ही चलते नजर आते है, जितने आमजन के चेहरे पर मुस्कान लाने की मुहिम में वे जुटे है। तभी तो जिस प्रकार साहित्य से आध्यत्मिकता व सामाजिकता के सफर में वे निरन्तर कार्य कर अपनी एक विशिष्ट पहचान बना चुके हैं, उसी प्रकार राजनीति क्षेत्र में भी उनकी पहचान कम नही है। उत्तराखंड में तिवारी शासनकाल में वे बीस सूत्रीय कार्यक्रम के राज्य सदस्य रहे और श्रेष्ठतम अवदान के लिए उन्हें मुख्यमंत्री ने सरकारी स्तर पर सम्मानित किया था। वे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के भी प्रवक्ता रहे है,साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमेश पोखरियाल निशंक के साहित्यिक मित्र भी है। उनकी गिनती दलगत राजनीति से ऊपर उठकर राज्य व देश हित की सोच रखने वालों में होती है।

उत्तराखंड में परिवार रजिस्टर की जांच के आदेश

2003 से 2026 तक परिवार रजिस्टर खंगाले जाएंगे

उत्तराखंड में परिवार/कुटुंब रजिस्टर को लेकर लंबे समय से उठते रहे सवालों और सामने आ रही अनियमितताओं के बीच राज्य की धामी सरकार ने अब निर्णायक कदम उठाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में वर्ष 2003 से जनवरी 2026 तक के सभी परिवार रजिस्टरों की व्यापक और गहन जांच के निर्देश दिए हैं। सरकार का मानना है कि बीते दो दशकों में रजिस्टर में हुई गलत प्रविष्टियों, फर्जी दस्तावेजों के इस्तेमाल और नियमों की अनदेखी ने न केवल प्रशासनिक व्यवस्था को कमजोर किया है, बल्कि इससे जन-सांख्यिकीय संतुलन पर भी असर पड़ने की आशंका है। इसी को देखते हुए सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि जांच के दौरान किसी भी स्तर पर गड़बड़ी या मिलीभगत सामने आने पर दोषियों के खिलाफ कठोर विभागीय और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह कार्रवाई केवल हालिया मामलों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि वर्षों से चली आ रही खामियों को उजागर कर व्यवस्था को पूरी तरह दुरुस्त करने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगी।

उत्तराखंड में परिवार/कुटुंब रजिस्टर से जुड़ी अनियमितताओं को लेकर राज्य सरकार ने अब बेहद सख्त और निर्णायक रुख अपना लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट कर दिया है कि इस महत्वपूर्ण अभिलेख व्यवस्था में किसी भी तरह की लापरवाही, गड़बड़ी या फर्जीवाड़ा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी क्रम में सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए प्रदेशभर के परिवार रजिस्टरों की वर्ष 2003 से जनवरी 2026 तक व्यापक और गहन जांच कराने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री का कहना है कि जांच के दौरान यदि किसी भी स्तर पर नियमों का उल्लंघन, गलत प्रविष्टि या फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल सामने आता है, तो संबंधित व्यक्तियों के साथ-साथ जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ भी कठोर विभागीय और कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। दरअसल, परिवार या कुटुंब रजिस्टर ग्रामीण व्यवस्था की रीढ़ माने जाते हैं। इन्हीं रजिस्टरों के आधार पर नागरिकों को निवास, परिवार पहचान, सामाजिक योजनाओं और विभिन्न सरकारी सुविधाओं का लाभ मिलता है। ऐसे में इन रजिस्टरों में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी न केवल प्रशासनिक व्यवस्था को कमजोर करती है, बल्कि इससे सामाजिक और जन-सांख्यिकीय संतुलन पर भी गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। पंचायती राज विभाग के आंकड़े भी इस चिंता को मजबूती देते हैं। बीते कुछ वर्षों में परिवार रजिस्टर से संबंधित सेवाओं के लिए बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से हजारों आवेदन नियमों के उल्लंघन, अपूर्ण दस्तावेजों और संदिग्ध तथ्यों के कारण निरस्त किए गए। सरकार का मानना है कि इतनी बड़ी संख्या में निरस्तीकरण इस बात का संकेत है कि व्यवस्था में कहीं न कहीं गंभीर खामियां मौजूद हैं, जिनकी अनदेखी अब संभव नहीं है। इसी पृष्ठभूमि में मुख्यमंत्री ने यह निर्देश दिए हैं कि परिवार रजिस्टरों की जांच का दायरा केवल हालिया वर्षों तक सीमित न रखा जाए, बल्कि वर्ष 2003 से अब तक की सभी प्रविष्टियों की समीक्षा की जाए। सरकार का तर्क है कि यदि केवल वर्तमान या हाल के मामलों की जांच की गई, तो वर्षों से चली आ रही अनियमितताएं सामने नहीं आ पाएंगी। पिछले दो दशकों में हुई संभावित गड़बड़ियों की पहचान कर उन्हें उजागर करना और दुरुस्त करना ही इस कवायद का मूल उद्देश्य है। मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों में कहा है कि जब तक पुरानी गलतियों को सामने लाकर उन पर कार्रवाई नहीं की जाएगी, तब तक व्यवस्था में स्थायी सुधार संभव नहीं है। जांच प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए सरकार ने अभिलेखों की सुरक्षा को भी सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि प्रदेश के सभी जिलों में उपलब्ध परिवार या कुटुंब रजिस्टरों की प्रतियां तत्काल संबंधित जिलाधिकारियों के पास सुरक्षित रखी जाएं। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जांच के दौरान या उससे पहले अभिलेखों में किसी भी तरह की छेड़छाड़ की संभावना पूरी तरह समाप्त हो जाए। सरकार का मानना है कि जब तक रिकॉर्ड पूरी तरह सुरक्षित नहीं होंगे, तब तक निष्पक्ष जांच संभव नहीं है। इसके साथ ही यह भी तय किया गया है कि परिवार रजिस्टरों की गहन जांच सीडीओ और एडीएम स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों से कराई जाएगी, ताकि प्रक्रिया पर किसी प्रकार का स्थानीय दबाव या प्रभाव न पड़ सके और जांच पूरी तरह प्रभावी ढंग से संपन्न हो। मुख्यमंत्री ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर परिवार रजिस्टर में नाम दर्ज कराने के मामलों को लेकर भी बेहद सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि यदि कोई व्यक्ति गलत या फर्जी दस्तावेजों के सहारे परिवार रजिस्टर में अपना या किसी अन्य का नाम दर्ज कराता पाया गया, तो उसके खिलाफ नियमानुसार कड़ी विभागीय और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इतना ही नहीं, यदि जांच के दौरान यह सामने आता है कि किसी अधिकारी या कर्मचारी ने लापरवाही बरती है या जानबूझकर मिलीभगत की है, तो उस पर भी कार्रवाई से पीछे नहीं हटा जाएगा। मुख्यमंत्री का कहना है कि कानून और नियम सभी के लिए समान हैं, चाहे वह आम नागरिक हो या सरकारी कर्मचारी। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि परिवार रजिस्टर में नए नाम जोड़ने की प्रक्रिया को अब और अधिक सख्त तथा पारदर्शी बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि परिवार रजिस्टर का पंजीकरण पंचायत राज (कुटुंब रजिस्टरों का अनुरक्षण) नियमावली, 1970 के तहत किया जाता है। इन नियमों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार

का नाम परिवार रजिस्टर में दर्ज होना अनिवार्य है। हालांकि, समय के साथ इस प्रक्रिया में कई स्तरों पर ढिलाई और अनियमितताओं की शिकायतें सामने आई हैं। अब सरकार का उद्देश्य है कि वर्तमान प्रविष्टियों का शुद्धिकरण किया जाए और भविष्य में नए नाम जोड़ने की प्रक्रिया पूरी तरह नियमबद्ध, सख्त और पारदर्शी हो। नियमों के अनुसार परिवार रजिस्टर में नाम दर्ज करने का अधिकार एडीओ पंचायत के पास होता है, जबकि किसी भी प्रकार की आपत्ति या विवाद की स्थिति में अपील एसडीम स्तर पर की जा सकती है। इसके अलावा, यह सेवाएं "अपणी सरकार" पोर्टल के माध्यम से भी उपलब्ध कराई गई हैं, ताकि नागरिकों को कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें और पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन व ट्रैक करने योग्य हो सके। सरकार का मानना है कि डिजिटल माध्यमों के अधिक उपयोग से न केवल पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि अनियमितताओं की गुंजाइश भी काफी हद तक कम होगी।

परिवार रजिस्टर में गड़बड़ी आने के बाद धामी सरकार ने लिया फैसला

मुख्यमंत्री ने परिवार रजिस्टर के मामलों में जन-सांख्यिकीय संतुलन के मुद्दे पर भी गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि बीते वर्षों में सीमावर्ती और मैदानी जिलों के कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में अनधिकृत बसावट के आधार पर परिवार रजिस्टर में नाम दर्ज होने की शिकायतें सामने आई हैं। इससे स्थानीय जनसंख्या संरचना और सामाजिक संतुलन प्रभावित होने की आशंका बनी हुई है। इसी कारण सरकार ने यह निर्णय लिया है कि प्रदेश के सभी जिलों में समान रूप से जांच कराई जाएगी, ताकि किसी भी क्षेत्र के साथ भेदभाव का आरोप न लगे और जांच प्रक्रिया निष्पक्ष बनी रहे। सरकार ने यह भी संकेत दिए हैं कि भविष्य में परिवार रजिस्टर से संबंधित एक स्पष्ट और व्यापक नीति तैयार की जाएगी, जिसे कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। इस नीति का उद्देश्य न केवल वर्तमान व्यवस्था को मजबूत करना होगा, बल्कि भविष्य में उत्पन्न होने वाली समस्याओं को भी पहले ही रोकना होगा। मुख्यमंत्री का कहना है कि परिवार रजिस्टर केवल एक प्रशासनिक दस्तावेज नहीं, बल्कि ग्रामीण समाज की पहचान और संरचना का आधार हैं। इसलिए इनकी शुद्धता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उत्तराखंड सरकार का यह कदम परिवार रजिस्टर व्यवस्था में पारदर्शिता, जवाबदेही और भरोसे को बहाल करने की दिशा में एक बड़ा और अहम प्रयास माना जा रहा है। सरकार ने साफ कर दिया है कि चाहे मामला कितना भी पुराना क्यों न हो, यदि उसमें गड़बड़ी पाई जाती है तो उस पर कार्रवाई अवश्य होगी। यह संदेश न केवल आम जनता के लिए है, बल्कि प्रशासनिक तंत्र के हर स्तर के लिए भी है कि अब नियमों से समझौता नहीं किया जाएगा और व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए कठोर फैसले लेने से सरकार पीछे नहीं हटेगी।

नीलम अग्रवाल मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आयोजित स्वास्थ्य जांच शिविर में 115 से अधिक लोगों की विभिन्न जांचें की गई

नीलम अग्रवाल मेमोरियल चौरिटेबल ट्रस्ट द्वारा न्यू कैंट रोड पर एक बहुउद्देशीय स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया स्वास्थ्य शिविर में एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, डॉक्टरों के साथ नेत्र रोग विशेषज्ञ दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा शिविर में आए हुए लाभार्थियों की जांच की गई शिविर में विभिन्न जांच निशुल्क की गई जिसमें मुख्य रूप से लिवर फंक्शन टेस्ट, थायराइड टेस्ट कोलेस्ट्रॉल ब्लड शुगर यूरिक एसिड हीमोग्लोबिन कैल्शियम ब्लड प्रेशर आदि जांच की गई इसके अतिरिक्त बीएमआई मशीन द्वारा कंप्लीट बॉडी फैट कंपोजिशन चेक किया गया शिविर में लाभार्थियों को एलोपैथिक आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक दवाई भी निशुल्क वितरित की गई शिविर का उद्घाटन माननीय कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी जी पूर्व मेयर सुनील उनियाल गामा जी पिछड़ा वर्ग आयोग के पूर्व अध्यक्ष अशोक वर्मा जी इंटरनेशनल वैश्य फेडरेशन के प्रांतीय अध्यक्ष दीपक सिंघल जी बालाजी सेवा समिति के अध्यक्ष अखिलेश अग्रवाल जी, पृथ्वीनाथ महादेव मंदिर के संजय गर्ग जी और क्षेत्रीय पार्षद भूपेंद्र कठैत जी द्वारा दीप प्रज्वलित कर और नीलम अग्रवाल जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर किया गया इस अवसर पर ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉ सुनील अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि ट्रस्ट द्वारा यह शिविर पूरी तरह से निशुल्क रखा गया और शिविर में 115 से अधिक लाभार्थियों की विभिन्न डॉक्टरों द्वारा और लैब टेस्ट द्वारा जांच की गई और डॉक्टरों द्वारा सुझाई गई एलोपैथिक आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक दवाई निशुल्क वितरित की गई उन्होंने बताया कि ट्रस्ट स्वास्थ्य सेवाओं हेतु निरंतर कार्य करता रहेगा और स्वस्थ समाज की अवधारणा हेतु निरंतर जन जागरण अभियान चलाएगा कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी जी ने ट्रस्ट के गठन की सराहना करते हुए ट्रस्ट के कार्य को समाज के लिए उल्लेखनीय उदाहरण बताया उन्होंने कहा की स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करना सच्ची जनसेवा है पूर्व मेयर सुनील उनियाल गामा जी एवं पिछड़ा वर्ग आयोग के पूर्व अध्यक्ष अशोक वर्मा जी ने भी ट्रस्ट के कार्यों की सराहना की स्वास्थ्य शिविर में मुख्य रूप से डॉक्टर नरेश भंडारी ,डॉक्टर एन एल अमोली, दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मयंक कोहली, नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ सिमरन भंडारी एवं डॉ गणेश गिरी, डॉ शैली गुप्ता एवं डॉक्टर रितु बडोनी बीएमआई मशीन टेक्निशियन गोपाल रावल, लैब टेक्नीशियन हिमानी राघव, प्रिंसी टम्टा, सृष्टि भट्ट सहयोगी अक्षय अग्रवाल सुरभि जैन महक गोयल अमित अग्रवाल शोभित जैन राघव गोयल का महत्वपूर्ण योगदान रहा शिविर में विभिन्न संस्थाओं से प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

वर्ष 2026: सुशासन, विकास और आत्मनिर्भर उत्तराखंड की दिशा में धामी सरकार

वर्ष 2026 उत्तराखंड के लिए परिणाम दिखाने का वर्ष होगा। हमारा उद्देश्य है कि सुशासन का लाभ हर नागरिक तक पहुंचे। पर्वतीय क्षेत्रों में पॉलीहाउस खेती, कीवी, सेब और अन्य उच्च मूल्य वाली फसलों को बढ़ावा देकर हम किसानों की आय को बढ़ाने पर विशेष फोकस रहेगा। युवाओं और महिलाओं को सशक्त बनाना हमारी प्राथमिकता है। सरकारी भर्तियों में पारदर्शिता के साथ-साथ स्टार्टअप, उद्योग और स्वरोजगार के अवसर बढ़ाए जा रहे हैं। महिला सशक्तिकरण और पर्यावरण संरक्षण पर विशेष ध्यान देंगे। हमारा लक्ष्य है कि उत्तराखंड सशक्त, सुरक्षित, आत्मनिर्भर और विकास के अवसरों से भरपूर राज्य बने जहां किसान समृद्ध हों, युवा आशावान हों और महिलाएं मुख्यधारा में सहभागी बनें।

-पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में वर्ष 2026 राज्य के विकास की दिशा में एक निर्णायक और परिणामोन्मुख वर्ष के रूप में रहने जा रहा है। ऐतिहासिक नीतिगत निर्णयों के बाद अब सरकार का मुख्य फोकस योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, जमीनी बदलाव और आम नागरिक की आय व जीवन स्तर में ठोस सुधार पर केंद्रित रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में वर्ष 2026 की कार्ययोजना सुशासन, समावेशी विकास, आर्थिक आत्मनिर्भरता, कृषि-उद्यानिकी सशक्तिकरण और पर्यावरण संतुलन के इर्द-गिर्द केंद्रित है।

सुशासन और प्रशासनिक सुधार: सरकार का प्राथमिक लक्ष्य शासन व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और तकनीक-आधारित बनाना है। वर्ष 2026 में ई-गवर्नेंस को सभी विभागों में अनिवार्य रूप से लागू करते हुए डिजिटल फाइल सिस्टम, ऑनलाइन सेवाओं और समयबद्ध डिलीवरी को सशक्त किया जाएगा। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति के तहत जन शिकायतों का त्वरित निस्तारण और सेवाओं की तय समय-सीमा में उपलब्धता सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है।

इन्फ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी: राज्य में सड़क, रेल और हवाई कनेक्टिविटी को मजबूती देना 2026 के एजेंडे का अहम स्तंभ है। चारधाम ऑल वेदर रोड, ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना, हेली सेवाओं का विस्तार और सीमावर्ती क्षेत्रों में रणनीतिक सड़कों के निर्माण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, ताकि पर्वतीय और दूरस्थ क्षेत्रों तक स्वास्थ्य, शिक्षा और आपात सेवाओं की आसान पहुंच सुनिश्चित हो सके।

उद्यानिकी, पॉलीहाउस और कीवी नीति-ग्रामीण अर्थव्यवस्था की नई रीढ़: वर्ष 2026 में धामी सरकार का सबसे सशक्त फोकस कृषि के साथ-साथ उद्यानिकी को आय बढ़ाने का मुख्य माध्यम बनाना है। इसके तहत पॉलीहाउस खेती, कीवी उत्पादन, हाई वैल्यू फसलों और सेब-कीवी नीति को विशेष प्राथमिकता दी जा रही है।

राज्य सरकार पर्वतीय क्षेत्रों में पॉलीहाउस आधारित खेती को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देगी, जिससे किसान वर्षभर सब्जी, फूल और उच्च गुणवत्ता वाली फसलें उगा सकें। पॉलीहाउस के लिए अनुदान, तकनीकी सहायता, प्रशिक्षण और बाजार से जोड़ने की व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा। कीवी मिशन/कीवी नीति के तहत उत्तराखंड को देश का प्रमुख कीवी उत्पादक राज्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। कीवी की खेती से कम भूमि में अधिक आय, बेहतर बाजार मूल्य और निर्यात की संभावनाएँ किसानों को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेंगी। इसके साथ ही सेब, नाशपाती, अखरोट और अन्य पहाड़ी फलों की वैल्यू चेन विकसित की जाएगी। सरकार का उद्देश्य है कि "खेती से आय" को दोगुना करने की दिशा में उद्यानिकी को मुख्य हथियार बनाया जाए, जिससे पलायन रुके और गांवों में ही रोजगार के अवसर सृजित हों।

पर्यटन: रोजगार और स्थानीय भागीदारी: पर्यटन को आर्थिक इंजन के रूप में विकसित करना 2026 की रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। चारधाम यात्रा को सुरक्षित और तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के साथ-साथ विंटर टूरिज्म, साहसिक पर्यटन, ईको-टूरिज्म और होमस्टे योजनाओं को प्रोत्साहन दिया जाएगा। स्थानीय युवाओं और महिलाओं की भागीदारी से पर्यटन आधारित रोजगार सृजन पर विशेष जोर रहेगा।

रोजगार, युवा और कौशल विकास: वर्ष 2026 में सरकारी भर्तियों को पूरी तरह पारदर्शी, समयबद्ध और नकलमुक्त बनाए रखने का संकल्प दोहराया गया है। निजी क्षेत्र में रोजगार बढ़ाने के लिए स्टार्टअप, आईटी पार्क, उद्योग और निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा। युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट, तकनीकी प्रशिक्षण और स्वरोजगार योजनाओं का विस्तार किया जाएगा।

महिला सशक्तिकरण और सामाजिक सुधार: समान नागरिक संहिता (UCC) के प्रभावी क्रियान्वयन के साथ महिला सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। स्वयं सहायता समूहों, लखपति दीदी योजना और महिला उद्यमिता को प्रोत्साहित कर महिलाओं को विकास की मुख्यधारा से जोड़ा जाएगा।

पर्यावरण संरक्षण और आपदा प्रबंधन: हिमालयी पारिस्थितिकी का संरक्षण, नदियों और जल स्रोतों का पुनर्जीवन, वनों की सुरक्षा और आपदा पूर्व चेतावनी प्रणालियों को मजबूत करना सरकार की दीर्घकालिक प्राथमिकताओं में शामिल है।

वर्ष 2026 मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार के लिए "नीतियों से परिणाम" का वर्ष होगा। उद्यानिकी, पॉलीहाउस और कीवी जैसी उच्च आय वाली योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देते हुए सरकार का लक्ष्य उत्तराखंड को एक सशक्त, आत्मनिर्भर और संतुलित विकास वाला राज्य बनाना है, जहाँ विकास और प्रकृति साथ-साथ आगे बढ़ें और हर नागरिक को समान अवसर मिले।

अब एक क्लिक पर मिलेगी मतदाताओं को 2003 की वोटर लिस्ट

अब 2003 की वोटर लिस्ट में नाम खोजना हुआ और भी आसान

- *गली, मोहल्लों या एरिया के नाम से खोज सकेंगे 2003 के पोलिंग बूथ*
- *मतदाताओं की सुविधा के लिए तैयार किया गया नया यूजर इंटरफेस*

मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ बीवीआरसी पुरुषोत्तम की पहल पर आगामी विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर प्रदेश में वर्ष 2003 की मतदाता सूची में नाम खोजने की प्रक्रिया को बेहद आसान बना दिया गया है। अब मतदाता केवल अपने गली, मोहल्ले एवं एरिया के नाम के आधार पर भी वर्ष 2003 की मतदाता सूची में अपना नाम खोज सकेंगे।

सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी मस्तू दास ने बताया कि प्रदेश में आगामी 10 जनवरी तक बीएलओ आउटरीच अभियान सम्पादित किया जा रहा है। इस अभियान के तहत बीएलओ घर-घर जाकर मतदाताओं से संपर्क कर उनकी 2003 की मतदाता सूची में जानकारी से मिलान कर रहे हैं। ऐसे में प्रदेश के कई मतदाता ऐसे हैं जिन्हें अपने वर्ष 2003 के बूथों की सही जानकारी नहीं हैं। मतदाताओं की इसी परेशानी को देखते हुए सीईओ उत्तराखण्ड की आधिकारिक वेबसाइट www.ceo.uk.gov.in पर 2003 की मतदाता सूची को और सरल विकल्प के साथ सर्च करने की सुविधा प्रदान की गई।

मतदाताओं की सुविधा के लिए वर्ष 2003 की मतदाता सूची पहले से ही मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखंड की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है, जहां मतदाता अपने विधानसभा क्षेत्र, अपने तथा अपने पिता/पति के नाम के आधार पर मतदाता क्रमांक एवं बूथ संख्या की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नए फीचर के साथ अब गली, मोहल्लों और एरिया के नाम से भी मतदाता सूची खोजी जा सकेगी।

सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने जन सामान्य से बीएलओ को अपेक्षित जानकारी उपलब्ध कराने की अपील की है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक मतदाता के मताधिकार की सुरक्षा के लिए बीएलओ द्वारा हर मतदाता से समन्वय, संवाद और पंहुच सुनिश्चित की जा रही है।

मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने सचिवालय में कार्बन क्रेडिट के सम्बन्ध में संबंधित विभागों के साथ बैठक की

मुख्य सचिव ने सम्बन्धित विभागों द्वारा कार्बन क्रेडिट की दिशा में किए जा रहे कार्यों की जानकारी ली। मुख्य सचिव ने कहा कि उत्तराखण्ड के लिए कार्बन क्रेडिट एक महत्त्वपूर्ण आय का श्रोत बन सकता है। इसके लिए विभागों को अपने-अपने कार्यक्षेत्र में सम्भावनाएं तलाशनी होंगी। साथ ही कार्बन क्रेडिट किस प्रकार से लिया जा सकता है उसके लिए तैयारियाँ करनी होगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पर्यावरण विभाग कार्बन क्रेडिट के लिए नोडल विभाग के रूप में कार्य करेगा। उन्होंने कहा कि शुरुवात में ऐसे लॉ हैंगिंग फ्रूट्स जिनमें आसानी से सफलता प्राप्त हो सकती है, पर कार्य शुरू किया जाए। मुख्य सचिव ने कहा कि उत्तराखण्ड में एक हजार इलेक्ट्रिक बसें शुरू की जा रही हैं। परिवहन विभाग को इलेक्ट्रिक बसों के माध्यम से कार्बन क्रेडिट का लाभ मिल सकता है। उन्होंने वन पंचायतों के माध्यम से वन विभाग और पैक्स (PACS) के माध्यम से सहकारिता विभाग कार्बन क्रेडिट अर्जित कर सकते हैं और उन्हें राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय बाजार में बेचकर अतिरिक्त आय प्राप्त कर सकते हैं। मुख्य सचिव ने पर्यावरण विभाग को शीघ्र ही कार्बन क्रेडिट के लिए नॉलेज पार्टनर के रूप में किसी एजेन्सी को अपने साथ शामिल किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी सम्बन्धित विभागों को भी आपसी सामंजस्य से इस दिशा में कार्य किए जाने की बात कही। इस अवसर पर प्रमुख सचिव श्री आर.के. सुधांशु एवं एपीसीसीएफ श्री एस.पी. सुबुद्धि सहित विभिन्न सम्बन्धित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी और नाबार्ड के उच्चाधिकारी उपस्थित थे।

प्रेस क्लब की नव निर्वाचित कार्यकारिणी ने अजय राणा के नेतृत्व में मुख्यमंत्री से की शिष्टाचार भेंट

मुख्यमंत्री ने पत्रकारों के हितों के लिए हर संभव सहयोग का दिया आश्वासन

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से गुरूवार को मुख्यमंत्री आवास में उत्तरांचल प्रेस क्लब की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के पदाधिकारियों ने अध्यक्ष अजय राणा के नेतृत्व में शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी भी मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री ने प्रेस क्लब के नव निर्वाचित पदाधिकारियों को शुभकामनाएं देते हुए सभी के उज्ज्वल भविष्य की कामना की। मुख्यमंत्री ने कहा लोकतंत्र में मीडिया का महत्व सर्वविदित है। मीडिया से जुड़े प्रतिनिधियों की समस्याओं के समाधान के लिये राज्य सरकार निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने मीडियाकर्मियों से राज्य विकास में सहयोगी बनने की भी अपेक्षा की।

इस अवसर पर प्रेस क्लब के निवर्तमान अध्यक्ष भूपेंद्र कंडारी ने कहा कि पूर्व में भी प्रेस क्लब को मुख्यमंत्री व सरकार का सहयोग मिलता रहा। उन्होंने उम्मीद जताई कि आगे भी इसी प्रकार का सहयोग मिलता रहेगा। नवनिर्वाचित अध्यक्ष अजय राणा और महामंत्री योगेश सेमवाल ने प्रेस क्लब भवन निर्माण के प्रस्ताव के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया।

मुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान प्रेस क्लब के कोषाध्यक्ष मनीष डंगवाल कार्यकारिणी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष गजेंद्र सिंह नेगी, कनिष्ठ उपाध्यक्ष सोबन सिंह गुसाई, संयुक्त मंत्री शिवेश शर्मा, मीना नेगी, संप्रेक्षक विजय जोशी, कार्यकारिणी सदस्य मनमोहन लखेड़ा, रश्मि खत्री, सुलोचना पयाल, वीरेंद्र डंगवाल, मनोज जयाडा, हरीश थपलियाल, मनवर सिंह रावत उपस्थित रहे।

जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वारः गुड गवर्नेंस का उत्तराखंड मॉडल

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि "जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार" कार्यक्रम प्रदेश में सुशासन, संवेदनशीलता और समाधान का सशक्त माध्यम बन चुका है। सरकार का संकल्प है कि कोई भी नागरिक योजनाओं और सेवाओं से वंचित न रहे। आज 31 दिसंबर 2025 तक प्रदेश के 13 जनपदों में 173 शिविरों का आयोजन किया गया, जिनमें 1,08,710 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए। इनमें से 15,730 आवेदनों का त्वरित निस्तारण किया गया तथा 11,493 से अधिक नागरिकों को प्रमाण-पत्र एवं सेवाएं मौके पर उपलब्ध कराई गई। इस अभियान के माध्यम से 63,202 से अधिक लोग विभिन्न सरकारी योजनाओं से लाभान्वित हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि यह अभियान केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जनता के विश्वास की पुनर्स्थापना और सरकार-जनता की दूरी को समाप्त करने का प्रयास है। प्रत्येक जनपद में प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि दिव्यांग, बुजुर्ग, महिलाओं और कमजोर वर्गों तक स्वयं पहुंचकर उनकी समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करें।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि "मेरी सरकार की प्राथमिकता है कि हर पात्र व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से पहुंचे। 'जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार' अभियान इसी सोच का परिणाम है। उत्तराखंड में सुशासन अब कागजों तक नहीं, बल्कि धरातल पर दिख रहा है।"

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि लंबित आवेदनों का समयबद्ध निस्तारण किया जाए। शिविरों की निरंतर मॉनिटरिंग हो,फील्ड स्तर पर संवेदनशील और जवाबदेह प्रशासन सुनिश्चित किया जाए, प्रदेश सरकार जनता के विश्वास के साथ सेवा, सुशासन और विकास के संकल्प को निरंतर आगे बढ़ा रही है।

नाबार्ड ने किया क्षेत्रीय सलाहकार समिति बैठक एवं जीआई कार्यशाला का आयोजन

- ***कार्यशाला में विभिन्न विभागों और योजनाओं के बीच अभिसरण पर जोर दिया गया ताकि जीआई आधारित ग्रामीण समृद्धि को बढ़ावा दिया जा सके***
- ***पद्मश्री डॉ. राजनिकांत (GI मैन ऑफ इंडिया) ने जीआई पंजीकरण, अधिकृत उपयोगकर्ता जोड़ने एवं पोस्ट-जीआई रणनीतियों पर मार्गदर्शन दिया***
- ***उत्तराखंड में नाबार्ड की सक्रिय भूमिका की सराहना की, जिसमें जीआई योग्य उत्पादों की पहचान, पंजीकरण, ब्रांडिंग एवं विपणन के प्रयास शामिल हैं।***

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा उत्तराखंड क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून ने दूसरी क्षेत्रीय सलाहकार समिति (RAC) बैठक एवं जीआई कार्यशाला का आयोजन 30 दिसंबर 2025 को अपने आईटी पार्क स्थित कार्यालय में किया। बैठक का विषय था- "ग्रामीण समृद्धि हेतु जीआई की क्षमता का उपयोग: ब्रांडिंग, विपणन एवं मूल्य संवर्धन के लिए पोस्ट-जीआई रणनीतियाँ।"

बैठक का शुभारंभ श्री पंकज यादव, मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड द्वारा किया गया। इस अवसर पर SLBCèk UKSRLMèk KVIC@ KVIB, कृषि एवं उद्यान विभाग, IIT रुड़की, IIT काशीपुर, UKSTCB, ग्रामीण विकास विभाग, NGOs सहित कई प्रमुख संस्थानों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। उत्तराखंड टी बोर्ड, DDMs एवं चैनल पार्टनर्स ने वर्चुअल माध्यम से सहभागिता की।

कार्यक्रम की विशेषता रही पद्मश्री डॉ. राजनिकांत (GI मैन ऑफ इंडिया) का ऑनलाइन तकनीकी सत्र। उन्होंने जीआई पंजीकरण, अधिकृत उपयोगकर्ता जोड़ने एवं पोस्ट-जीआई रणनीतियों पर मार्गदर्शन दिया और उत्तराखंड में नाबार्ड की सक्रिय भूमिका की सराहना की, जिसमें जीआई योग्य उत्पादों की पहचान, पंजीकरण, ब्रांडिंग एवं विपणन के प्रयास शामिल हैं।

बैठक के दौरान विशेषज्ञों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और स्टार्टअप्स की भूमिका पर सुझाव दिए कि वे जीआई उत्पादों के प्रचार, ब्रांडिंग और बाजार विस्तार में कैसे योगदान दे सकते हैं। बैठक में विभिन्न विभागों और योजनाओं के बीच अभिसरण पर भी जोर दिया गया ताकि जीआई आधारित ग्रामीण समृद्धि को बढ़ावा दिया जा सके। नाबार्ड ने यह संकल्प दोहराया कि वह ग्रामीण समुदायों को जीआई संवर्धन, ब्रांडिंग सहायता, प्रशिक्षण और बाजार संपर्क के माध्यम से सशक्त करेगा, जिससे उत्तराखंड के पारंपरिक उत्पादों को राष्ट्रीय और वैश्विक पहचान मिल सके।

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हाउस ऑफ हिमालयाज की 6वीं बोर्ड बैठक का सफल आयोजन

मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में हाउस ऑफ हिमालयाज की 6वीं बोर्ड बैठक आयोजित हुयी। बैठक के दौरान अध्यक्ष श्री आनन्द बर्द्धन एवं निदेशक मंडल द्वारा विभिन्न प्रस्तावों को स्वीकृति दी गयी। अपर सचिव एवं एमडी सुश्री झरना कमठान ने हाउस ऑफ हिमालयाज की अब तक की प्रगति की विस्तृत जानकारी दी।

मुख्य सचिव ने कहा कि हाउस ऑफ हिमालयाज से अधिक से अधिक क्लस्टर लेवल फेडरेशन्स एवं स्वयं सहायता समूहों को जोड़ कर हाउस ऑफ हिमालयाज में शामिल किया जान चाहिए। उन्होंने क्लस्टर लेवल फेडरेशन्स और स्वयं सहायता समूहों को और अधिक मजबूत किए जाने पर जोर दिया। उन्होंने निर्देश दिए कि सीएलएफ एवं स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों का भुगतान को प्राथमिकता पर लेते हुए उनका भुगतान शीघ्र से शीघ्र किया जाए। उत्पादों की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए जीआई टैगिंग और जैविक प्रमाणीकरण के महत्त्व पर बल देते हुए उन्होंने जीआई टैगिंग और जैविक प्रमाणीकरण की दिशा में कार्य किए जाने के निर्देश दिए। साथ ही, उत्पादों के एमआरपी निर्धारित किए जाने के लिए मैकेनिज्म तैयार किए जाने की भी बात कही।

मुख्य सचिव ने हाउस ऑफ हिमालयाज को अपने वेयरहाउस और स्टोरेज क्षमता बढ़ाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हाउस ऑफ हिमालयाज का वेयरहाउस गढ़वाल एवं कुमाऊं के साथ ही, एक बड़ा वेयरहाउस हब राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली एवं एनसीआर में भी होना चाहिए। इसके लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। मुख्य सचिव ने रॉ मैटीरियल एवं उत्पादों के लिए सगन्ध पौधा केन्द्र एवं दून सिल्क फेडरेशन के साथ शीघ्र एमओयू किए जाने की बात भी कही। उन्होंने एयरपोर्ट्स एवं मैट्रो स्टेशनों में आउटलेट्स बढ़ाए जाने के साथ ही अलग-अलग राज्यों में बन रहे यूनिटी मॉल्स में हाउस ऑफ हिमालयाज के उत्पादों के लिए आउटलेट्स स्थापित किए जाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आउटलेट्स को उत्पाद बिक्री के लक्ष्य प्रदान किए जाएं। साथ ही अच्छा कर रहे आउटलेट्स को इंसेटिव भी प्रदान किया जाए, ताकि बाकी आउटलेट कर्मी भी प्रेरित हों।

अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जाँच हेतु गदरपुर ऊधमसिंह नगर में प्रदर्शन

अंकिता भंडारी हत्याकांड आज भी केवल एक परिवार का निजी दुख नहीं, बल्कि पूरे उत्तराखंड की आत्मा, बेटियों की सुरक्षा और हमारी न्याय व्यवस्था पर लगा एक गहरा सवाल है।

जब महीनों बाद भी पीड़ित परिवार न्याय की प्रतीक्षा में है और सच तक पहुँचने की राह बार-बार रोकी जा रही है, तब प्रदेश सरकार की चुप्पी और टालमटोल वाला रवैया असहनीय हो जाता है।

न्याय तभी सार्थक होगा जब इस जघन्य अपराध की स्वतंत्र, निष्पक्ष ब्ठप् जांच हो और अपराधी चाहे कितने ही रसूखदार क्यों न हों, उन्हें कानून के अनुसार कठोरतम सजा मिले।

इसी संकल्प और उत्तराखंड की बेटियों के सम्मान की रक्षा के लिए आज गदरपुर तहसील के बाहर जुलूस एवं धरना-प्रदर्शन कर सरकार की जवाबदेही तय करने का स्पष्ट संदेश दिया गया।

यह संघर्ष किसी राजनीतिक दल का नहीं, बल्कि सच, इंसाफ और भविष्य की पीढ़ियों की सुरक्षा का संघर्ष है और यह आवाज तब तक उठती रहेगी, जब तक अंकिता को पूरा न्याय नहीं मिल जाता।

दिल्ली में भी आयोजित होगा उत्तराखंड माल्टा महोत्सव : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री ने किया उत्तराखंड माल्टा महोत्सव का शुभारंभ

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को राजकीय उद्यान सर्किट हाउस गढ़ीकैंट में उत्तराखंड माल्टा महोत्सव का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राज्य में माल्टा के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए माल्टा मिशन शुरू करने की घोषणा करते हुए कहा कि दिल्ली में भी राज्य की ओर से माल्टा महोत्सव का आयोजन किया जायेगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री धामी ने अपनी धर्मपत्नी श्रीमती गीता पुष्कर धामी के साथ विभिन्न जनपदों के माल्टा एवं नींबू प्रजाति के फलों की प्रदर्शनी का अवलोकन कर माल्टा एवं नींबू की खटाई सहित नींबू प्रजाति के फलों से बने विभिन्न उत्पादों का स्वाद भी लिया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि माल्टा उत्तराखंड की पहचान एवं परंपरा से जुड़ा है। राज्य की आर्थिकी व समृद्धि को सशक्त करने में बागवानी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इन्हीं संभावनाओं को साकार करने के लिए राज्य सरकार ने एप्पल मिशन व कीवी मिशन जैसी कई उल्लेखनीय शुरूआत की है। इसी तर्ज पर राज्य में माल्टा के उत्पादन को बढावा देने के लिए माल्टा मिशन की शुरूआत की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के माल्टा की ब्रांडिंग व इसे बेहतर बाजार उपलब्ध कराने के लिए भी सरकार के द्वारा अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। राज्य के हर जनपद में माल्टा महोत्सव का आयोजन इन्हीं प्रयासों की एक कड़ी है। उन्होंने कहा कि राज्य के माल्टा को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए दिल्ली में भी राज्य की ओर से माल्टा महोत्सव का आयोजन किया जायेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में किसानों की आर्थिकी को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। खेती व बागवानी के क्षेत्र में समुचित प्रोत्साहन, नवाचार और आधुनिक तकनीकों के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाई जा रही है। यह पहल पलायन रोकने और युवाओं को अपने गांव के पास ही रोजगार देने में गेम चेंजर साबित होगी।

जानिए कैसा होगा आपका यह सप्ताह

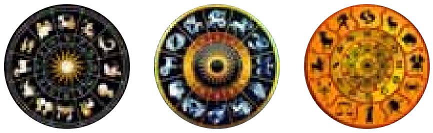

पं. दीपक प्रसाद, शास्त्री (मो. 9557730042)
(ज्योतिष, कर्मकाण्ड, धर्मिक अनुष्ठान आदि)

मेष राशि- स्वास्थ्य थोड़ा नरम होने की वजह से आपके कुछ काम अधूरे रह सकते हैं पर चिंता न करें। परिवार के सदस्यों का पूरा सहयोग आपके साथ बना रहेगा। पड़ोसियों के साथ किसी भी तरह के वाद-विवाद में न पड़ें। अपने विचारों और स्वभाव में संयम रखना आपके लिए बहुत जरूरी है। भाग्यशाली रंग- हरा, भाग्यशाली अंक- 2

वृषभ राशि- वर्तमान में चल रही गतिविधियों पर ही अपना पूरा ध्यान रखें। पार्टनरशिप जैसा कोई नया काम शुरू करने के लिए अभी समय आपके पक्ष में नहीं है। कोई पुरानी रुकी हुई पेमेंट या उधार दिया हुआ पैसा आज समय पर मिल जाएगा। नौकरीपेशा लोगों को अपनी कार्यप्रणाली में बदलाव से अच्छे परिणाम मिलेंगे। भाग्यशाली रंग- लाल, भाग्यशाली अंक- 1

मिथुन राशि- आप बिजनेस से जुड़ा कोई नया काम शुरू करने वाले हैं, तो किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह जरूर लें। जल्दबाजी में लिया गया फैसला आपका काम बिगाड़ सकता है। इस समय मेहनत ज्यादा और लाभ थोड़ा कम रहने वाली स्थिति बनी रहेगी। पब्लिक डीलिंग से जुड़े कामों पर आज ज्यादा ध्यान दें। भाग्यशाली रंग- आसमानी, भाग्यशाली अंक- 8

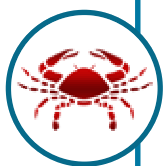

कर्क राशि- कार्यस्थल पर कर्मचारियों की वजह से आ रही समस्याओं को आप अपनी सूझबूझ से सुलझा लेंगे। प्रॉपर्टी से जुड़ी आज कोई बहुत अच्छी डील फाइनल हो सकती है। नौकरीपेशा लोग अपने बॉस और अधिकारियों के साथ संबंध अच्छे रखें। आपकी कड़ी मेहनत जल्दी ही आपको लक्ष्य तक पहुंचाएगी। भाग्यशाली रंग- बादामी, भाग्यशाली अंक- 5

सिंह राशि- अपनी व्यस्तता के साथ-साथ परिवार की जरूरतों का ध्यान रखना भी आपका बड़ा कर्तव्य है। अपने लव पार्टनर को कोई छोटा सा उपहार जरूर दें, इससे रिश्तों में मिठास आएगी। प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी और एक-दूसरे के प्रति लगाव बढ़ेगा। मानसिक शांति के लिए मेडिटेशन जरूर करें। भाग्यशाली रंग- सफेद, भाग्यशाली अंक- 4

कन्या राशि- पार्टनरशिप से जुड़ी योजनाओं को पूरा करने के लिए यह बहुत ही अनुकूल समय है। इस समय बिजनेस में आपको कुछ नए और अच्छे प्रस्ताव मिलेंगे। कार्यभार थोड़ा ज्यादा बना रहेगा। नौकरीपेशा लोगों को काम में किसी गलती की वजह से मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए सावधान रहें। भाग्यशाली रंग- नीला, भाग्यशाली अंक- 7

तुला राशि- यह समय आपके लिए बहुत ही सावधानी से बिताने का है। बिजनेस में कुछ आर्थिक नुकसान होने जैसी स्थिति बन रही है इसलिए पूरी तरह सतर्क रहें। पार्टनरशिप वाले कामों में भी संभलकर व्यवहार करने की जरूरत है। नौकरीपेशा लोगों पर आज काम का दबाव ज्यादा रह सकता है। भाग्यशाली रंग- केसरिया, भाग्यशाली अंक- 3

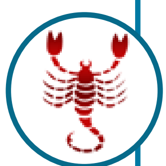

वृश्चिक राशि- आर्थिक स्थिति आज सामान्य ही बनी रहेगी। व्यक्तिगत कामों में बहुत ज्यादा व्यस्त रहने की वजह से आपके कई जरूरी काम अधूरे रह सकते हैं। सरकारी नौकरी करने वालों को आज अतिरिक्त कार्यभार संभालना पड़ सकता है। आप अपने आत्मविश्वास के बल पर हर काम समय पर पूरा कर लेंगे। भाग्यशाली रंग- बैंगनी, भाग्यशाली अंक- 4

धनु राशि- बिजनेस की कार्यप्रणाली को बेहतर बनाने के लिए बनाई गई आपकी योजनाएं आज सफल होंगी। पार्टनरशिप से जुड़ा कोई नया काम शुरू करने के लिए यह बहुत ही उत्तम समय है। मार्केटिंग से जुड़ी गतिविधियां आज बढ़ सकती हैं। राजनीति से जुड़े लोगों और कामों से खुद को दूर रखें। भाग्यशाली रंग- सफेद, भाग्यशाली अंक- 7

मकर राशि- पारिवारिक माहौल बहुत ही सुखद और शांतिपूर्ण बना रहेगा। युवा वर्ग प्रेम संबंधों के बजाय अभी अपने करियर और भविष्य पर ज्यादा ध्यान दें। जीवनसाथी के साथ आपसी तालमेल घर की व्यवस्था को और भी ज्यादा मजबूत बनाएगा। सिर दर्द और माइग्रेन की समस्या आज आपको परेशान कर सकती है। भाग्यशाली रंग- गुलाबी, भाग्यशाली अंक- 9

कुंभ राशि- आपकी कामयाबी को देखकर कुछ लोग आपसे जलन की भावना रख सकते हैं। निवेश या इन्वेस्टमेंट से जुड़े कामों में किसी की बातों में न आएं और खुद पूरी जांच-पड़ताल जरूर करें। अपने स्वभाव में धैर्य और सहजता बनाए रखना आज आपके लिए बहुत जरूरी होगा। भाग्यशाली रंग- लाल, भाग्यशाली अंक- 1

मीन राशि- कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले परिस्थितियों की पूरी जानकारी जरूर लें वरना कोई आपकी भावनाओं का गलत फायदा उठा सकता है। युवा वर्ग अपने भविष्य और करियर पर ज्यादा ध्यान दें। जोश में आकर किसी से भी ऐसा वादा न करें जिसे पूरा करना आपके लिए मुश्किल हो। भाग्यशाली रंग- हरा, भाग्यशाली अंक- 6

R.N.I.: UTTHIN/2010/41629 | Postal Regd. UA/DO/DDN/01/2025-2027